The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 7 | July 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

बदलते आधुनिक परिदृश्य में भारत-पाकिस्तान संबंध की प्रासंगिकता

डॉ विजय कुमार
(सहायक आचार्य) रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
ममता कन्नौजिया (शोधार्थी)रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16850791

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-07-2025

Published: 10-08-2025

Keywords:

भारत-पाकिस्तान संबंध, आतंकवाद, कश्मीर विवाद, भू-राजनीति, आर्थिक सहयोग, परमाणु निवारण

ABSTRACT

भारत और पाकिस्तान के संबंधों का एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है, जो संघर्षों, राजनयिक तनावों और सुलह के प्रयासों से भरा है। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में, इन संबंधों की प्रासंगिकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गतिशीलता को सीधे प्रभावित करते हैं। आधुनिक युग में भारत-पाक संबंधों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। बेहतर संबंधों के संभावित लाभ दोनों देशों से कहीं आगे बढ़कर क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक संघर्षों और राजनीतिक जटिलताओं के बावजूद, राजनयिक प्रयास, आर्थिक सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संपर्क दक्षिण एशिया में अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह शोध अध्ययन भारत की विदेश नीति व कूटनीति पर इन प्रतिक्रियाओं के प्रभाव, भारत-पाक संबंधों में उठाए गए सकारात्मक कदमों के असर, और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद पर बढ़ते दबाव जैसे विषयों पर केंद्रित है। यह विश्लेषण इन जटिल गतिशीलता को समझने और आगे की राह तलाशने का प्रयास करता है।

प्रस्तावना

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध, जो 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के साथ शुरू हुए थे, इतिहास, भूगोल, विचारधारा और सुरक्षा चिंताओं के एक जटिल जाल में गहराई से उलझे हुए हैं। यह लेख बदलते आधुनिक भू-राजनीतिक परिदृश्य में इन संबंधों की निरंतर प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है, जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि व्यापक वैश्विक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध जटिल और शत्रुतापूर्ण रहे हैं,

जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन और हिंसा हुई है। इस विभाजन का मूल कारण "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" में निहित है, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की, यह मानते हुए कि हिंदू और मुसलमान एक राज्य में एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। जूनागढ़ और कश्मीर जैसी रियासतों के विलय को लेकर शुरुआती विवादों ने भविष्य के संघर्षों के बीज बो दिए। विशेष रूप से कश्मीर, जो एक मुस्लिम-बहुल रियासत थी जिस पर एक हिंदू राजा का शासन था, जिसका भारत में विलय पाकिस्तान द्वारा अवैध करार दिया गया था।

आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में इस संबंध की निरंतर प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए यह संबंध बेहद खतरनाक है; संघर्ष बढ़ने की संभावना क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए भारत-पाकिस्तान संबंधों का सामान्यीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की कुल आबादी का पाँचवाँ हिस्सा रहता है। इसके अलावा, वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के वर्तमान दौर में, जिसमें महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी शामिल है, भारत के लिए अपने सीमावर्ती पड़ोसियों से परे व्यापक वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभाना अनिवार्य है, लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध इस व्यापक भूमिका को प्रभावित करते हैं।

यह लेख इस संबंध की ऐतिहासिक उत्पत्ति, प्रमुख द्विपक्षीय आयामों (सुरक्षा, आर्थिक, जल, लोगों से लोगों के बीच संपर्क, कूटनीतिक), बदलती वैश्विक भू-राजनीति के प्रभाव और अंततः, आधुनिक परिदृश्य में इसकी निरंतर प्रासंगिकता, साथ ही चुनौतियों, अवसरों और आगे की राह के सुझावों का आकलन करेगा।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष केवल सीमा विवादों या सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान के मूल में गहरे वैचारिक मतभेदों से प्रेरित है। विभाजन "द्वि-राष्ट्र सिद्धांत" पर आधारित था, और कश्मीर विवाद तुरंत उत्पन्न हुआ क्योंकि पाकिस्तान इसे अपनी वैचारिक पहचान का एक हिस्सा मानता था। यह केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए "इस्लाम खतरे में" की धारणा से "पाकिस्तान खतरे में" में बदल गया, जिससे भारत के प्रति स्थायी शत्रुता पैदा हुई। पाकिस्तान कश्मीर विवाद को अपनी पहचान और भारत के प्रति "बदले" की भावना से जोड़ता है। यह स्थिति शांति वार्ता को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना देती है, क्योंकि यह केवल राजनीतिक रियायतों का मामला नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आत्म-धारणा का मामला है। इसलिए, जब तक पाकिस्तान की रणनीतिक सोच में एक बुनियादी वैचारिक बदलाव नहीं आता, सतही विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) या वार्ताओं का सीमित प्रभाव ही होगा। यह संघर्ष को "अ-रणनीतिक" बना देता है, जिसका कोई तर्कसंगत अंत नज़र नहीं आता, फिर भी भारत को नुकसान पहुँचाने की भावनात्मक इच्छा के कारण यह जारी है।

वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान संबंध

आधुनिक युग में किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय हित के संबंध में उसके पड़ोसी देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि पड़ोसी देश के साथ संबंध मधुर होंगे तो राष्ट्रीय हित संवारा जा सकता है। भारत–पाक संबंध 1947, यानी आज़ादी के साथ ही, तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी न किसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते रहते हैं। यदि पिछले सभी मुद्दों का आकलन किया जाए तो कुछ के परिणाम स्पष्ट हुए, लेकिन कश्मीर विवाद आज भी इन संबंधों में कड़वाहट का बीज बना हुआ है। विभाजन के सात दशक बाद भी यह स्पष्ट है कि इसका मूल उद्देश्य अधूरा है। यह माना गया था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनने से दोनों देशों में शांति और सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।[1]

भारत और पाकिस्तान के पहले राजनयिक नेतृत्व—पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना—की अपेक्षा थी कि दोनों राष्ट्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत को कई बार युद्ध के लिए ललकारा, जिनमें से 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्ध प्रमुख हैं।[2] जब पाकिस्तान को यह अनुभव हुआ कि भारत पर पारंपरिक युद्ध में विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, तो उसने छद्म युद्ध और आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया।[3] 21वीं सदी में भारत–पाक संबंध शांतिपूर्ण नहीं रह सके, बल्कि आतंकवाद और सीमा पर संघर्ष की घटनाएं लगातार होती रहीं।

राजनीतिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान दो भिन्न राष्ट्र हैं, लेकिन सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों में गहरी समानता है।[4] इसके बावजूद दोनों अच्छे पड़ोसी या मित्र राष्ट्र नहीं बन सके। यह चिंताजनक है कि इतने समानताओं के बाद भी दोनों देशों के बीच शत्रुता बनी हुई है।

इतिहास इस बात का गवाह है कि 1947, 1965, 1971 और 1999 में दोनों देशों के बीच युद्ध हो चुके हैं। लेकिन इन युद्धों से भी राजनीतिक नेतृत्व ने कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला[5]। मोदी सरकार के पहले भी मतभेदों को सुलझाने के लिए संयुक्त मैकेनिज्म बनाए गए, लेकिन पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकवाद ने हर बार इन प्रयासों को विफल किया।[6]

प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन शपथग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को आमंत्रित कर उन्होंने संबंधों में सुधार की संभावना दिखाई। इसके पश्चात 25 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने अचानक लाहौर जाकर शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी, जिससे उम्मीद बनी कि तनाव में कमी आएगी। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ।[7] इसके बाद उरी हमला (18 सितंबर 2016) हुआ, जो पाकिस्तान प्रायोजित था। इन घटनाओं के बाद भारत ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाले SAARC सम्मेलन का बहिष्कार किया, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, और मालदीव ने भी भारत का साथ दिया।[8] इससे स्पष्ट हुआ कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ-साथ दक्षिण एशिया के अन्य देशों से सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाना चाहती है।

दूसरी ओर, चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण किया है और "वन बेल्ट वन रोड" परियोजना के तहत चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को विकसित किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर

गुजरता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।[9] इसके अतिरिक्त, चीन इस क्षेत्र में सैनिक भी तैनात कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है।

चीन–पाकिस्तान–रूस के बढ़ते रणनीतिक समीकरण भी भारत के हितों को प्रभावित कर रहे हैं।[10] भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में अपने शपथ समारोह में SAARC देशों के नेताओं के साथ मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया, जो इस बात का संकेत था कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक रूप से सक्रिय और संवेदनशील है। लेकिन भारत के लिए सबसे कठिन कार्य यह है कि उसे पाकिस्तान और चीन जैसे दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के साथ तनावपूर्ण वातावरण में अपने हितों की रक्षा करनी है। चीन हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थलों पर बंदरगाह बना रहा है और भारत को समुद्री मार्गों से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसे "मोतियों की माला" (String of Pearls) नीति कहा जाता है।[11]

बालाकोट के बाद की चुनौतियां

14 फरवरी 2019 को पुलवामा में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के 40 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के केवल दो सप्ताह के भीतर, भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हवाई सर्जिकल स्ट्राइक की।[12] भारत ने 2016 के उरी हमले के बाद यह रणनीतिक सिद्धांत स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवादी हमलों का उत्तर अब केवल राजनयिक विरोध से नहीं दिया जाएगा, बल्कि सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प होगा। बालाकोट स्ट्राइक उसी नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है।[13] इस कार्रवाई के बाद भारत में यह विमर्श तेज हुआ कि पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जाए। भारत-पाक संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं हैं, बल्कि इनका प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता, सामाजिक ताने-बाने और आर्थिक नीति पर भी पड़ता है।[14] हालांकि, इस घटनाक्रम में मूल समस्या - आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, यह प्रश्न कहीं पीछे छूट गया। बालाकोट जैसी कार्रवाई से भारत की सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन हुआ, लेकिन आतंकवाद के दीर्घकालिक समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति आवश्यक है।[15] इसमें केवल सैन्य उत्तर नहीं, बल्कि आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण पर रोक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना भी शामिल होना चाहिए। यह लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं, विचारधारा और समाज के भीतर भी लड़ी जानी है।

आतंक का लॉन्च पैड पाकिस्तान

पाकिस्तान लंबे समय से इस बात से इनकार करता रहा है कि वह आतंकवाद के वैश्विक फैलाव में किसी भी प्रकार की भूमिका निभा रहा है। लेकिन वास्तविकता इससे ठीक उलट है। पाकिस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, और जमात-उद-दावा जैसे संगठनों को अपने यहाँ सुरक्षित पनाहगाहें उपलब्ध करवाई हैं।[16] इन आतंकी संगठनों की गतिविधियाँ पाकिस्तान की ज़मीन पर बिना किसी रोक-टोक के चलती रही हैं, जिससे वह एक आतंकवाद का लॉन्च पैड बन चुका है। इन्हीं संगठनों ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला (26/11), 2016 में उरी हमला और 2019 में

पुलवामा हमला किया।[17] ये सभी हमले न केवल भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती थे, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक अप्रत्यक्ष उपकरण बन चुका है।

पाकिस्तान आतंकवादी हमलों की ज़िम्मेदारी से बचने के लिए बार-बार सबूतों को नकारता रहा है। किन्तु भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पुख़्ता साक्ष्यों के साथ पाकिस्तान को बेनक़ाब किया है।[18] फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल कर यह संकेत दिया कि आतंकवाद को शह देने वाले देशों के लिए वैश्विक समुदाय में कोई स्थान नहीं है। आज वैश्विक जगत की समझ में यह बात आ चुकी है कि पाकिस्तान चाहे प्रत्यक्ष रूप से इन आतंकियों को समर्थन दे या न दे, लेकिन उनका संरक्षण और सहूलियतें निश्चित रूप से वहाँ उपलब्ध हैं। यह स्थिति केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है।[19]

भारत की पारंपरिक प्रतिक्रिया

भारत की आतंकी घटनाओं के प्रति पारंपरिक प्रतिक्रिया प्रायः रक्षात्मक और कूटनीतिक रही है। हर बड़े हमले के बाद, जनता की आक्रोशित भावनाओं को शांति और नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने राजनयिक और राजनीतिक उपायों का सहारा लिया है।[20] भारत ने लम्बे समय तक यह मान लिया था कि आतंकवाद एक सीमापार घुसपैठ की समस्या है, न कि एक रणनीतिक खतरा। इसलिए भारत की नीति वार्ता, सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान पर केंद्रित रही है।[21]

भारत ने बार-बार यह प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के ज़रिए विवादित मुद्दों का समाधान निकाला जाए और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उदाहरण के लिए, भारत ने पाकिस्तान से MFN (Most Favoured Nation) का दर्जा वापस ले लिया, खेल आयोजनों में पाकिस्तानी टीमों को वीज़ा देने से मना किया, और सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियों के जल के प्रयोग पर कड़ा रुख अपनाया।[22]

इन सभी कूटनीतिक और आर्थिक दबावों के बावजूद, पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर कोई प्रभावी रोक लगाने की पहल नहीं की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की पारंपरिक प्रतिक्रिया आतंकवाद से निपटने के लिए अपर्याप्त रही है, और इससे पाकिस्तान के व्यवहार में कोई गंभीर परिवर्तन नहीं आया।[23]

भारत की रणनीति में बदलाव

उरी हमले (18 सितंबर 2016) के बाद भारत की रक्षा रणनीति में एक ऐतिहासिक और निर्णायक परिवर्तन देखने को मिला। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हुए, जिसके उत्तर में भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों (लॉन्च पैड्स) को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया।[24] यह एक ऐसी रणनीतिक सफलता थी जिसमें भारत ने प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर घेर लिया और उसे यह कहने का अवसर नहीं मिला कि उसका कोई संबंध नहीं है।

भारत की इस नीति से भारत-पाक संबंधों में सैन्य तनाव तो बढ़ा, लेकिन साथ ही भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरी। हालांकि, यह भी एक जोखिम भरा कदम था क्योंकि पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और इस प्रकार की सैन्य कार्यवाही से क्षेत्रीय शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था।[25] इसके बावजूद भारत ने संयम की पारंपरिक नीति को त्याग कर यह स्पष्ट कर दिया कि वह अब आतंक के खिलाफ हरसंभव कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे इसके पीछे कितना भी खतरा क्यों न हो। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही केवल आतंकियों के विरुद्ध है, पाकिस्तान के आम नागरिकों या उसकी सेना को लक्ष्य नहीं बनाया गया।[26] यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत ने अपनी नैतिक स्थिति बनाए रखी। इसके पश्चात पुलवामा आतंकी हमले (14 फरवरी 2019) में 40 CRPF जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने एक और निर्णायक कदम उठाया। बालाकोट एयरस्ट्राइक (26 फरवरी 2019) में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर जाकर जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया।[27] यह 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर आतंक के विरुद्ध कार्यवाही की। यह भी एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र की वायुसेना ने दूसरे परमाणु संपन्न राष्ट्र की सीमाओं में घुसकर पारंपरिक रणनीतिक बमबारी की।[28] इस रणनीति परिवर्तन ने भारत की सुरक्षा नीति को "रक्षात्मक संयम" से "नियंत्रित आक्रामकता" की ओर मोड़ दिया है, जिसमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध को वैध और आवश्यक माना जा रहा है।

भारत-पाक संबंध उठाए गए सकारात्मक कदम

वर्तमान में पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसमें भुगतान संतुलन की समस्या, विदेशी ऋण का बढ़ता बोझ और बढ़ती मुद्रास्फीति प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 2024 तक उसकी GDP के 74.5% तक पहुँच गया है।[29] पुलवामा आतंकी हमले (14 फरवरी 2019) के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आयात होने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क 200% तक बढ़ा दिया, जिससे पाकिस्तान के निर्यात को भारी झटका लगा और उसकी अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हुई।[30] इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को दी गई मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) की स्थिति को भी समाप्त कर दिया था।[31] भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली भारतीय संविधान की धारा 370 को अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार संबंध समाप्त कर दिए।[32] इससे पाकिस्तान के व्यापारिक समुदाय और नागरिकों में आर्थिक असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो गया। हालांकि कटुता के इस दौर में भी कुछ सकारात्मक पहल देखने को मिलीं। भारत ने पाकिस्तान द्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर निर्माण की योजना का समर्थन किया। यह गलियारा 2019 में शुरू हुआ, जिससे भारत के सिख श्रद्धालुओं को बिना वीजा पाकिस्तान के पवित्र गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुँचने की सुविधा मिली।[33] यह पहल "पीपल-टू-पीपल कॉन्टेक्ट" को बढ़ावा देती है और दोनों देशों के नागरिकों के बीच विश्वास निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की सक्रियता भी भारत-पाक संबंधों पर निर्भर करती है। दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव के चलते 2016 के बाद से सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हो पाया है।[34] इस संगठन को पुनः सक्रिय करने के लिए भारत

और पाकिस्तान को पारस्परिक पहल की आवश्यकता है, जिससे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास को गति मिल सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाइयों के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंधों में अनेक स्थायी और संरचनात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद और ऐतिहासिक घटनाओं की भिन्न व्याख्याएँ, द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। भारत को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खतरा है, जिसके समाधान हेतु उसे अपने सभी राष्ट्रीय शक्ति तत्वों – कूटनीति, सैन्य शक्ति, आर्थिक साधन, सूचना युद्ध और जनसंपर्क – का समन्वित उपयोग करना होगा। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे पर भ्रम फैलाता रहा है, जबकि उसके भीतर आतंकी संगठनों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसलिए भारत को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निरंतर यह संदेश देना होगा कि वह पाकिस्तान की धरती से संचालित किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा, और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्ष कार्रवाई भी करेगा। भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिलता को देखते हुए, भविष्य की राह में अनेक चुनौतियाँ तथा सीमित अवसर निहित हैं। इनसे निपटने के लिए एक बहुआयामी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) के हालिया अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में शीघ्र सुधार की संभावना न्यून है, क्योंकि 2016 के बाद से कोई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, और कश्मीर, आतंकवाद, एवं राजनीतिक तनाव जैसे कारक अब भी प्रभावी बने हुए हैं।[35] भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, वहीं पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता भी द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की उसकी क्षमता को बाधित करती है। इस परिप्रेक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तावित "आर्थिक अन्योन्याश्रयता की रणनीति" एक उपयोगी मॉडल साबित हो सकती है, जिसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों – जैसे गुजरात, राजस्थान और पंजाब – में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने हेतु निवेश किया जा सकता है। इससे दोनों देशों की सीमावर्ती अर्थव्यवस्थाओं को गति मिल सकती है, और भारत को अपनी आर्थिक श्रेष्ठता का लाभ कूटनीतिक रूप से उठाने का अवसर भी मिलेगा। यदि पाकिस्तान भारत को पुनः "मोस्ट फेवर्ड नेशन" (MFN) का दर्जा देता है, तो आर्थिक सहयोग की संभावनाएँ और बढ़ सकती हैं।[36] इसके साथ ही, खुले संवाद को बढ़ावा देने, संकट प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष व सुरक्षित संचार तंत्र विकसित करने, और संघर्ष विराम समझौतों को प्रभावी रूप से लागू करने जैसे कदम भी उठाने होंगे। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान, खेल आयोजनों, जलवायु परिवर्तन व स्वास्थ्य जैसे साझा मुद्दों पर सहयोग की संभावनाओं को भी सशक्त करना होगा। इसके अतिरिक्त, सार्क जैसे क्षेत्रीय मंचों को पुनः सक्रिय कर वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है।[37] साथ ही, दोनों देशों को यह भी समझना होगा कि बाह्य शक्तियों – जैसे अमेरिका और चीन – के साथ द्विपक्षीय संबंधों को संभालने में संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जिससे कि भारत-पाक संबंध बाहरी प्रभाव से प्रभावित न हों।

भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान से सामान्य और शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, परंतु वह अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में, भारत को एक द्विदिशीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा और विकास दोनों का संतुलित सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो। केवल सुरक्षा आधारित या केवल आर्थिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होगा। सुरक्षा चिंताओं को सुलझाए बिना आर्थिक सहयोग टिकाऊ नहीं रह पाएगा, और आर्थिक लाभों के बिना संवाद की प्रेरणा भी कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए भारत को अपनी आतंकवाद विरोधी कठोर नीति बनाए रखते हुए, व्यापार, जल सहयोग, और सांस्कृतिक संबंधों जैसे विवाद रहित क्षेत्रों में विश्वास निर्माण की दिशा में सतत प्रयास करने होंगे। यही रणनीति "शीत शांति" (cold peace) से "कार्यात्मक शांति" (functional peace) की ओर एक सार्थक कदम हो सकती है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रश्न है, भारत ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि भारत-पाक संबंध केवल द्विपक्षीय प्रयासों के माध्यम से ही सुधर सकते हैं। भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, और उसका स्पष्ट मानना है कि सैन्य व राजनयिक चैनलों के माध्यम से ही समाधान की दिशा में पहल की जानी चाहिए। जब तक पाकिस्तान विशेषकर उसकी सैन्य संस्थाएं अपनी रणनीतिक सोच में बदलाव नहीं लातीं, तब तक किसी बाहरी मध्यस्थ का हस्तक्षेप परिणामदायक नहीं हो सकता।[38]

इस प्रकार, भविष्य की राह चुनौतीपूर्ण अवश्य है, परंतु यदि भारत एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाए जिसमें रणनीतिक दृढ़ता के साथ-साथ व्यावहारिक सहयोग की संभावनाएं भी तलाश की जाएं, तो भारत-पाक संबंधों में संतुलन, स्थिरता और सीमित सहयोग की एक नई संकल्पना साकार हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. Jalal, A. (1994). The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan. Cambridge University Press.

2. Ganguly, S. (2002). Conflict Unending: India–Pakistan Tensions Since 1947. Columbia University Press

3. Riedel, B. (2012). Deadly Embrace: Pakistan, America, and the Future of Global Jihad. Brookings Institution Press.

4. Malone, D. M., Mohan, C. R., & Raghavan, S. (2015). The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy. Oxford University Press.

5. Schofield, V. (2010). Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War (2nd ed.). I.B. Tauris.

6. Pant, H. V. (2016). Indian Foreign Policy: An Overview. Manchester University Press.

7. Joshi, M. (2017). Understanding the Pathankot Attack: Terrorism, Strategy and India's Response. ORF Issue Brief No. 164.

8. Malone, D. M., et al. (2015). The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy. Oxford University Press.

9. Small, A. (2015). The China-Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics. Oxford University Press.

10. Brewster, D. (2014). India's Ocean: The Story of India's Bid for Regional Leadership. Routledge.

11. Ibid.

12. Ministry of Defence. (2019). Balakot Airstrike Report. Government of India.

13. Rajagopalan, R. P. (2019). "India's Military Response Post-Uri and Balakot." The Diplomat.

14. Tellis, A. J. (2020). Terrorism and Indo-Pak Relations. Carnegie Endowment.

15. Singh, R. (2021). "Counterterrorism Strategies in South Asia." IDSA Briefs.

16. Fair, C. Christine (2019). In Their Own Words: Understanding Lashkar-e-Tayyaba. Oxford University Press.

17. Ministry of Home Affairs, India. (2019). Chronology of Major Terrorist Attacks on India. Government of India.

18. United Nations Security Council Reports. (2020). Sanctions Monitoring Team Reports on Pakistan.

19. FATF (2021). Jurisdictions under Increased Monitoring – Pakistan.

20. Pant, Harsh V. (2016). Indian Foreign Policy and National Security. ORF Occasional Paper.

21. Bajpai, Kanti. (2020). India Versus Pakistan: Why Can't We Just Be Friends? Juggernaut Books.

22. Ministry of External Affairs, India. (2019). India's Response to Pulwama Attack. Government White Paper.

23. Cohen, Stephen P. (2013). Shooting for a Century: The India-Pakistan Conundrum. Brookings Institution Press.

24. Ministry of External Affairs, Government of India. (2016). Statement on Surgical Strikes along the Line of Control.

25. Pant, Harsh V. (2017). India's Changing Pakistan Policy: Surgical Strikes and Beyond, Observer Research Foundation.

26. Press Information Bureau, Government of India. (2016). DGMO Briefing on Surgical Strikes.

27. Indian Air Force Report. (2019). Balakot Air Strikes Official Briefing.

28. Riedel, Bruce. (2020). Avoiding Armageddon: America, India and Pakistan to the Brink and Back, Brookings Institution Press.

29. International Monetary Fund (IMF). (2024). Pakistan Economic Outlook Report.

30. Ministry of Commerce & Industry, Government of India. (2019). Trade Measures Post-Pulwama Attack.

31. The Hindu. (2019). India withdraws MFN status to Pakistan after Pulwama attack.

32. Dawn News (2019). Pakistan suspends trade ties with India over Article 370 abrogation.

33. Ministry of External Affairs, Govt. of India. (2019). Kartarpur Corridor Agreement Signing.

34. SAARC Secretariat Report. (2022). Status of Summits and Future Prospects.

35. Centre for Policy Research, India-Pakistan Dialogue Tracker, 2024.

36. Ministry of Commerce, Government of India, Annual Trade Report with Pakistan, 2023.

37. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Summit Status Report, 2023.

38. Ministry of External Affairs, Government of India, Press Briefings on Third-Party Mediation Rejection, 2023.